संक्षिप्त समाचार

दिल्ली थोक बाजार में गेहूं, चावल में नरमी, दालों में गिरावट

नयी दिल्ली। दिल्ली थोक जिंस बाजार में शुक्रवार को अनाज और दालों में कुल मिला कर हल्की से लेकर औसत स्तर की गिरावट दिखी जबकि खाद्य तेलों के बाजार में रुझान मिला जुला था। बाजार में सामान्य क्वालिटी का चावल 33 रुपये प्रति क्विंटल नरम था, जबकि गेहूं दड़ा कल की तुलना में14 रुपये नीचे बोला जा रहा था। आटा में भी हल्की नरमी दिखी। दालों में अरहर प्रति क्विंटल 75 रुपये टूट गयी जबकि दाल चना, उड़द, मूंग और मसूर में भी 23 से 30 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखी गयी। खाद्य तेलों के थोक सौदों में सरसों तेल प्रतिक्विंटल 38 रुपये मंदा चल रहा था, वनस्पति में 37 रुपये और सोया तेल में 12 रुपये तक की नरमी दिखी। इसके विपरीत सूरज मुखी ओर पाम ऑयल के भाव लगभग 55 रुपये प्रति क्विंटल तेज चल रहे थे। तेल मूंगफली 21 रुपये चढ़ा हुआ था। विदेशी बाजारों में बुरसा (मलेशिया) बाजार में मई के वायादा अनुबंधों में भाव 23 रिंगिट बढ़ कर 4564 रिंगिट प्रति टन के स्तर पर चल रहा था। पिछले कई दिनों से पाम ऑयल वायदा में तेजी बनी हुई है। अमेरिकी जिंस बाजार में सोया तेल 0.03 सेंट यानी (0.04 प्रतिशत) की तेजी के साथ 67.45 सेंट प्रति पौंड के भाव पर था। गुड़ और चीनी में नरमी के रुझान के बीच कीमतें हल्के दबाव में थीं।

फरवरी में यात्री वाहन बिक्री 4.17 लाख पार, दोपहिया वाहनों में 35 प्रतिशत वृद्धि

नई दिल्ली। भारत में फरवरी 2026 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत बढ़कर 4,17,705 यूनिट्स हो गई है, जो फरवरी 2025 में 3,77,689 यूनिट्स थी। यह जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने शुक्रवार को दी। एसयूवी की मांग में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसकी बिक्री 2,36,957 यूनिट्स रही। वहीं कारों की थोक बिक्री में 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और यह 1,06,799 यूनिट्स रही। वैन की बिक्री 11,620 यूनिट्स रही, जो पिछली साल के समान अवधि की तुलना में मामूली वृद्धि है। दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री फरवरी में 35.2 प्रतिशत बढ़कर 18,71,406 यूनिट्स हुई, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री 29 प्रतिशत बढ़कर 74,573 यूनिट्स रही। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि उद्योग में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और फरवरी में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला पर असर डाल सकता है, जिससे विनिर्माण और निर्यात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इस वृद्धि के पीछे एसयूवी की मजबूत मांग, सकारात्मक बाजार सेंटीमेंट और त्योहारों का असर मुख्य कारण रहे।

सोने में मुनाफावसूली जारी, दाम 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसला

मुंबई। सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। इससे सोने का दाम फिर से 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे और चांदी की कीमत 2.60 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे लुढ़क गई है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से दोपहर 12 बजे जारी की गई कीमतों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का दाम 1,748 रुपए कम होकर 1,58,555 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,60,303 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट सोने का दाम 1,46,838 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,45,236 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,20,227 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,18,916 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

चांदी की कीमत 8,350 रुपए कम होकर 2,59,951 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 2,68,301 रुपए प्रति किलो थी। आईबीजेए की ओर से दिन दो बार दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे कीमतें जारी की जाती हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स), पर दोपहर 12:30 बजे, सोने के 2 अप्रैल, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,59,632 रुपए और चांदी के 5 मई, 2026 के कॉन्ट्रैक्ट 1.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,63,099 रुपए पर थे। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी जा रही है। सोना 0.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,092 डॉलर प्रति औंस और चांदी 3 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82 डॉलर प्रति औंस पर है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर जारी संघर्ष में तनाव के चलते सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई। वहीं, ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रास्फीति की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हो रही है। इससे सोने पर दबाव बढ़ रहा है।

केवी रमना मूर्ति सेबी के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

मुंबई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 1991 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर और पूर्व एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, कोम्पेला वेंकटा (केवी) रमना मूर्ति को तीन साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मूर्ति की नियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या अगले आदेश तक की अवधि के लिए मंजूरी दी। इससे पहले, मूर्ति सेबी बोर्ड में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में अंशकालिक सदस्य रहे हैं।

उनकी नियुक्ति के साथ, पिछले वर्ष रिक्तियों के बाद सेबी बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या चार हो गई है। अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संदीप प्रधान और अमरजीत सिंह शामिल हैं। बोर्ड में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने 1 मार्च, 2025 को पदभार ग्रहण किया। पूर्णकालिक सदस्य पूंजी बाजारों के विकास, जांच और नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांडे ने कहा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड देश की आर्थिक मजबूती में योगदान दे रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा, रसद और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में वित्तपोषण में मदद कर सकते हैं।

आम उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, कंपनियां रोज कर रहीं आपूर्ति की समीक्षा

संकट के बीच एलपीजी सप्लाई बनाए रखने की कोशिश जारी : नितिन खारा

नागपुर। ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक तनावों के बीच देश में एलपीजी आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित कंपनियां लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन नितिन खारा ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण एलपीजी सप्लाई को लेकर चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन कंपनी की प्राथमिकता देश के डीलरों और उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति बनाए रखना है।

नितिन खारा ने आईएएनएस को बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में एलपीजी की सप्लाई को लेकर रोजाना स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी रोज सुबह यह आकलन करती है कि उस दिन गैस की आपूर्ति किस तरह सुनिश्चित की जाए। दिनभर देश भर से डीलरों के फोन आते रहते हैं और कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि हर डीलर तक समय पर गैस पहुंचाई जा सके। हालांकि उपलब्धता में कमी के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि एलपीजी आयात करने वाली कंपनियों के सामने फिलहाल एक बड़ी समस्या यह है कि दो एलपीजी वेसल समुद्री बंदरगाहों के पास रुके हुए हैं और वे न तो अंदर आ पा रहे हैं और न ही बाहर जा पा रहे हैं। इसके कारण नियमित आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर कंपनी हर महीने करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी का आयात करती है, लेकिन मौजूदा हालात के कारण इसमें व्यवधान आया है।

फिलहाल लगभग 11,200 मीट्रिक टन एलपीजी का एक वेसल भारत पहुंच चुका है। नितिन खारा ने आगे बताया कि इस खेप में से करीब 850 मीट्रिक टन गैस खाली करने की योजना थी, जबकि बाकी गैस को मलेशिया की कंपनी इक्विनोर के साथ हुए एक कमिटमेंट के तहत आपूर्ति करने की बात थी। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक सेल-पर्चेज एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी अपने कमिटमेंट को निभाने के पक्ष में रहती है। उन्होंने कहा कि इस बीच कई डीलरों ने कंपनी से अनुरोध किया कि यह गैस भारत के नागरिकों और घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस बात पर विचार कर रही है कि उपलब्ध गैस का उपयोग देश में ही किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से भी सुझाव दिया गया है कि यह गैस स्थानीय स्तर पर ही उतारी जाए ताकि आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सके। खारा ने आगे कहा कि यदि यह एलपीजी देश में ही उपलब्ध हो जाती है तो इससे कम से कम 12 से 13 दिनों तक अतिरिक्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे बाजार में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

नितिन खारा ने बताया कि मौजूदा वैश्विक हालात और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आज ही हालात सामान्य हो जाएं तब भी पूरी स्थिति को सामान्य होने में लगभग चार महीने का समय लग सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कई रिफाइनरियों को नुकसान हुआ है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले रिफाइनरियों में उत्पादन शुरू होगा, फिर उस गैस को एलपीजी वेसल के जरिए विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल एलपीजी वेसल की भी भारी कमी है, जिससे आपूर्ति चक्र प्रभावित हो रहा है। उत्पादन, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया सामान्य होने में समय लगेगा। नितिन खारा ने भरोसा जताया कि सभी संबंधित कंपनियां और सरकारें मिलकर स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की दिशा में काम कर रही हैं। उनका कहना है कि कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि देश के आम नागरिकों तक एलपीजी की आपूर्ति बनी रहे और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ा, सेंसेक्स, निफ्टी में दो प्रतिशत तक की गिरावट

मुंबई। ईरान युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में गहराते संकट के बीच भारत के शेयर बाजारों में तेज गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और प्रमुख सूचकांकों में दो प्रतिशत या उससे अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गयी। पश्चिम एशिया की स्थिति से ईंधन और मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिताओं के चलते आज स्थानीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली दिखी। विश्लेषकों के अनुसार मार्जिन मनी का दबाव बढ़ने से निवेशकों को अपने अल्पकालिक दबाव से निपटने के लिए बिकवाली करनी पड़ रही है।

इन सबके सम्मिलित प्रभाव से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 प्रमुख शेयरों वाला निफ्टी-50 कल की तुलना में 488.05 अंक यानी 2.06 प्रतिशत गिर कर 23151.10 अंक पर बंद हुआ। बीएसई30 सेंसेक्स में 1470.50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी और यह 74563.92 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान बीएसई30 शुरू में ही बड़ी गिरावट के साथ 75,444.22 पर खुलने के बाद सुधर कर 75,576.20 तक गया लेकिन लेकिन यह तेजी टिकी नहीं और लगातार गिरावट के बीच एक समय दिन के न्यूनतम 74,454.60 पर पहुंचने के बाद अंत में 74,563.92 पर बंद हुआ। कल सेंसेक्स करीब एक प्रतिशत गिरावट के साथ 76,034.42 पर बंद हुआ था।

भारत में डेटा सेंटर क्षमता 2020 के बाद 4 गुना बढ़कर करीब 1,500 मेगावाट हुईः सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज संसद को बताया कि भारत का डेटा सेंटर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता 2020 में करीब 375 मेगावाट थी, जो 2025 तक चार गुना बढ़कर लगभग 1,500 मेगावाट हो गई है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई कंप्यूट क्षमता ढांचे के तहत 14 पंजीकृत सेवा प्रदाताओं और डेटा सेंटरों के माध्यम से लगभग 38,231 जीपीयू उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटिंग संसाधन स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य पात्र उपयोगकर्ताओं को औसतन 65 रुपए प्रति घंटे की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो वैश्विक औसत लागत का लगभग एक-तिहाई है।

देश के प्रमुख तकनीकी केंद्रों जैसे मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर में डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार डेटा

सेंटर इकोसिस्टम की बढ़ती जरूरतों, जैसे बिजली और पानी की मांग, से पूरी तरह अवगत है।

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, डेटा सेंटर से बिजली की मांग 2031-32 तक बढ़कर लगभग 13.56 गीगावाट तक पहुंच सकती है, क्योंकि एआई और बड़े पैमाने की कंप्यूटिंग सेवाओं के साथ यह क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है।

उन्होंने बताया कि देश की राष्ट्रीय ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि बढ़ती बिजली मांग को पूरा किया जा सके और सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। हाल ही में लागू किया गया सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (एसएचएएनटीआई) एक्ट भी भविष्य में छोटे मॉड्यूलर और माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टरों के उपयोग को संभव बनाकर एआई और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मंत्री ने बताया कि डेटा सेंटर में पानी की खपत इस्तेमाल की जाने वाली कूलिंग तकनीक पर निर्भर करती है।

उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर जैसे औद्योगिक उपयोगों के लिए भूजल के इस्तेमाल को जल शक्ति मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। पानी की खपत कम करने के लिए उद्योग अब डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग और इमर्शन कूलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कंपनियां हाई-डेंसिटी रैक सिस्टम भी लगा रही हैं ताकि हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई वर्कलोड को बेहतर तरीके से संभाला जा सके और बिजली व पानी की खपत भी कम हो।

भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान फिच ने बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया

नई दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.5 प्रतिशत किया है, जो पहले के 7.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी और फरवरी में आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी मंदी के बावजूद घरेलू मांग की मजबूती आर्थिक विकास को सहारा दे रही है। फिच के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में उपभोक्ता खर्च लगभग 8.6 प्रतिशत और निवेश लगभग 6.9 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। जीएसटी संग्रह, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, हवाई यात्रा और डिजिटल भुगतान जैसे संकेतक दिखाते हैं कि वैश्विक मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी और फरवरी के पीएमआई आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती दर्शाते हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अभी भी दो अंकों में बनी हुई है। फिच का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में महंगाई बढ़ने से वृद्धि दर थोड़ी धीमी रह सकती है, जबकि दूसरी छमाही में निवेश में तेजी आने की संभावना है। अनुमान है कि 2026-27 में भारत की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत और 2027-28 में 6.5 प्रतिशत रह सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2026 में लगभग 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि अमेरिका और चीन की वृद्धि क्रमशः 2.2 और 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

असम का जोहा चावल पहुंचा ब्रिटेन, इटली; एपीडा ने की मदद

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने असम से ब्रिटेन और इटली को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग वाले 25 टन जोहा चावल की पहली निर्यात खेप भेजने में सहायता की है।

वाणिज्य मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जोहा चावल की यह खेप असम सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से 12 मार्च को रवाना की गई।

असम की एक स्वदेशी सुगंधित किस्म, जोहा चावल को 2017 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ। अपनी विशिष्ट सुगंध, महीन दानेदार बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाने वाला यह चावल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों में पहचान अर्जित कर रहा है।

असम में, लगभग 21,662 हेक्टेयर क्षेत्र में जोहा चावल की खेती की जाती है, जिसका वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित उत्पादन लगभग 43,298 टन है। प्रमुख उत्पादक जिलों में नागांव, बक्सा, गोलपारा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट शामिल हैं, जो निर्यात विस्तार के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की प्रबल संभावना प्रदान करते हैं।

एपीडा जोहा चावल की वैश्विक उपस्थिति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले, प्राधिकरण ने जीआई-टैग वाले एक टन जोहा चावल के वियतनाम और दो टन को मध्य पूर्वी देशों - कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब में निर्यात की सुविधा प्रदान की थी।

असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने असम सरकार की कृषि उत्पादन आयुक्त अरुणा राजोरिया (आईएएस), एआरआईएएस सोसाइटी के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र मित्तल (आईएएस), असम सरकार के कृषि निदेशक डॉ. उदय प्रवीण (आईएएस), एपीईडीए के अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव, पादप संगरोध विभाग, कृषि विभाग और एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के अधिकारियों की उपस्थिति में निर्यात खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह निर्यात एपीडा में पंजीकृत निर्यातक मेसर्स सेफ एग्रीट्रेड प्रा.लि. कोलकाता द्वारा किया जा रहा है। खेप की प्रोसेसिंग और पैकिंग असम के गुवाहाटी स्थित प्रतीक एग्रो फूड प्रोसेसिंग में की गई है।

देश में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड 200 मिलियन टन : केंद्र

मुंबई। कोयला मंत्रालय ने आज बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 11 मार्च तक कैप्टिव, वाणिज्यिक और अन्य कोयला खदानों ने 200 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन का मील पत्थर पार कर लिया।

कुल उत्पादन में से, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों का योगदान 194.17 एमटी रहा, जबकि अन्य खदानों का योगदान 6.06 एमटी रहा, जिससे कुल उत्पादन ऐतिहासिक 200 एमटी के आंकड़े को पार कर गया।

विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2025-26 में कोयले का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 (197.32 एमटी) के कुल उत्पादन को 7 मार्च, 2026 को ही पार कर गया, और यह उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में 24 दिन पहले ही हासिल कर ली गई।

इस क्षेत्र ने अपनी मजबूत गति को बरकरार रखते हुए इसी अवधि

में वार्षिक आधार पर 10.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

मंत्रालय ने कहा, यह उपलब्धि विभिन्न केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू/एसपीएसयू) के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के सामूहिक प्रयासों और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिनके अथक परिश्रम और दृढ़ता ने देश के कोयला उत्पादन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोयले की आपूर्ति में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो वार्षिक आधार पर 7.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 182.98 एमटी से बढ़कर 197.09 एमटी हो गया है।

सरकार के अनुसार, कोयले के वितरण में यह निरंतर वृद्धि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों को विश्वसनीय कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।

मंत्रालय ने कहा कि वह भारत के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख चालक के रूप में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूरदर्शी नीतियों, तकनीकी नवाचार और खनन कार्यबल के समर्पण के बल पर, यह क्षेत्र राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान लगातार बढ़ा रहा है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि ये उपलब्धियां विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सुदृढ़ करने में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती हैं, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। इस वर्ष घरेलू कोयला उत्पादन और आपूर्ति खपत से अधिक रही है, जिसके परिणामस्वरूप खानों और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

कोविड के बाद भारत का लिस्टेड आरईआईटी मार्केट 1.72 लाख करोड़ तक पहुंचा

नई दिल्ली । कोविड-19 के बाद भारत का सूचीबद्ध रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) बाजार तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020 में इसका आकार 27,100 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह जानकारी सीबीआरई की रिपोर्ट में सामने आई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस वृद्धि का मुख्य कारण नए आरईआईटी की लिस्टिंग और पहले से मौजूद आरईआईटी के यूनिट प्राइस में लगातार बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही से लेकर 2026 की तीसरी तिमाही तक चार आरईआईटी ने सालाना 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की। सीबीआरई के चेयरमैन अंशुमन मैगजीन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारतीय आरईआईटी निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे रहा है। 2026 और उसके बाद आरईआईटी के उपयोग को बढ़ाने के लिए तीन महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव किए जा रहे हैं। एसईबीआई ने जनवरी से आरईआईटी को हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की जगह इक्विटी से जुड़े निवेश साधन के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे म्यूचुअल फंड और विशेष निवेश फंड की भागीदारी बढ़ेगी।

स्पेशल खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं-सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध

वित्त वर्ष 26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अनुरूप रहेगा

- वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान के दायरे में रखने का भरोसा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा-सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध।
- वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए आर्थिक स्थिरीकरण कोष बनाने का प्रस्ताव।
- पश्चिम एशिया के तनाव से ऊर्जा और आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है असर।
- सरकार आपूर्ति बाधाओं और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार।

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार वित्त वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटे को संशोधित अनुमानों के अनुरूप रखेगी। संसद में सीतारमण ने कहा कि अतिरिक्त खर्च के प्रस्ताव के बाद भी राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 27 के बजट में घोषित किए गए संशोधित लक्ष्य के अनुरूप ही रहेगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकार राजकोषीय अनुशासन और राजकोषीय समेकन को लेकर प्रतिबद्ध बनी हुई है।

वित्त मंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी के बाद उठाए गए कदमों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूती हुई है और साथ ही, वैश्विक झटकों के बाद भी राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की देश की क्षमता भी बढ़ी है।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का प्रस्ताव रखा, जो देश कों वैश्विक आर्थिक झटकों का मजबूती से सामना करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय क्षमता प्रदान करेगा।

सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित फंड अप्रत्याशित वैश्विक संकटों जैसे आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, किसी बड़े संकट के चलते अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को होने वाले नुकसान और अन्य बाहरी झटकों से निपटने के लिए सरकार की राजकोषीय हेडरूम प्रदान करेगा।

इस फंड का उद्देश्य हाल के अंतरराष्ट्रीय संकटों जैसी वैश्विक अनिश्चितता की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करना है।

इस फंड को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों की आशंका में सरकार द्वारा आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। साथ ही कहा कि सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

सीतारामण ने आगे कहा कि सरकार आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और एलपीजी सहित ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित संभावित चुनौतियों जैसे मुद्दों से निपटने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि भारत का मजबूत व्यापक आर्थिक ढांचा देश को राजकोषीय स्थिरता से समझौता किए बिना बाहरी झटकों का सामना करने में सक्षम बनाता है।